



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub section (ii)

आधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26, 1983/फाल्गुन 7, 1904  
No. 95] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26, 1983/PHALGUNA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1983

का. आ. 147(अ).—राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधि-  
नियम, 1946 (1948 का 11) के अधीन प्रयोज्य कृत्यों को, जहां तक ऐसे कृत्यों  
का सम्बन्ध न्यूनतम मजदूरी पर नियतन और क्रमशः बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी  
बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाट, मद्रास, नागालैण्ड,  
हरियाणा, मंमूर, राजस्थान, असम, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में स्थित किसी  
खदान में पत्थर तोड़ने या पत्थर दगने में नियोजित कर्मचारियों के लिए इस प्रकार  
निर्धारित की गई न्यूनतम दरों के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण से है, जिन्हें ऊपर  
नामित राज्यों की सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 253 के खंड (1) द्वारा प्रवृत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के तारीख 30 नवम्बर, 1968 को राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 4266, तारीख 25 नवम्बर, 1968 द्वारा यह कृत्य सौंप गए थे, वापस लेते हैं।

[सं. एस-32019/26/82-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.) 1]

एम. एल. मेहता, अव्वर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1983

**S.O. 147(E).**—The President is hereby pleased to withdraw the functions exercisable by the Central Government under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in so far as such functions relate to the fixation of minimum rates of wages and the review and revision of minimum rates so fixed, for employees employed in stone breaking or stone crushing operations carried on in any quarry situated within the respective States of Bihar, Maharashtra, West Bengal, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa, Kerala, Madras, Nagaland, Haryana, Mysore, Rajasthan, Assam, Andhra Pradesh and Gujarat, entrusted to the Government of the States named above, in exercise of powers conferred by clause (1) of the Article 258 of the Constitution under Notification bearing S.O. 4296 dated November 25, 1968 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 30th November, 1968.

[No. S-32019/26/82-W.C.(M.W.)]

M. L. MEHTA, Under Secy.